क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्षः 02 अंकः 85, शुक्रवार, 19 अप्रैल, 2019, पेजः 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिसः- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

भाजपा आज कर सकती है दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

नई दिल्ली। भाजपा ने दिल्ली की कुल सात लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह प्रक्रिया ऐसे समय में तेज हुई है जब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के गठबंधन की संभावनाएं अधर में हैं। सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी को बुधवार को उम्मीदवार चयन के लिए होने वाली एक अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए वापस बुलाया गया है। भाजपा के एक शीर्ष नेता ने कहा कि पार्टी गठबंधन से जुड़े घटनाक्रम पर ''पैनी नजर रखे हुए है, लेकिन वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, ''आप-कांग्रेस गठबंधन की स्थिति में कुछ सामंजस्य बनाना पड़ सकता है। लेकिन बदतर से बदतर स्थिति में भी सिर्फ 2-3 मौजूदा सांसदों की जगह नए चेहरे लाए जा सकते हैं। दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 अप्रैल है। गौरतलब है कि 'आप नेता संजय सिंह ने आज गठबंधन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने के बाद मीडिया को बताया कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर पूर्णविराम लग चुका है, इसलिए 'आप अकेले चुनाव लड़ेगी। सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन करने से इनकार कर दिया है और हम सिर्फ दिल्ली में गठबंधन नहीं करना चाहते।

'मोदी जी की सेना बयान पर नकवी को चुनाव आयोग की चेतावनी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव प्रचार में सैन्य बलों से जुड़े बयान देने पर गुरुवार को चेतावनी देते हुये भविष्य में उनसे इस तरह का बयान देने से बचने को कहा है। आयोग ने बृहस्पतिवार को पारित आदेश में नकवी को चेतावनी देते हुए कहा कि वह भविष्य में इस तरह के बयान देने से बचें। उल्लेखनीय है कि नकवी ने तीन अप्रैल को रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए 'मोदी जी की सेना शब्द का इस्तेमाल किया था। इस बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताने वाली शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने नकवी से जवाब-तलब किया था। नकवी द्वारा आठ अप्रैल को दिये गये जवाब के आधार पर आयोग ने कहा कि उनका बयान इस मामले में राजनीतिक दलों के लिये जारी पूर्व आदेश और परामर्श के अनुरूप नहीं है। आयोग ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और नेताओं को परामर्श जारी कर कहा था कि वे सैन्य बलों के पराक्रम से राजनीतिक अथवा चुनावी लाभ लेने के उद्देश्य से सेना और जवानों का चुनाव अभियान में जिक्र करने से बचें। आयोग के प्रमुख सचिव अनुज जयपुरिया ने आदेश में नकवी को चेतावनी दी है कि वह सैन्य बलों का राजनीतिक अभियान में जिक्र न करें और भविष्य में इस बारे में सचेत रहें।

सरदार पटेल की प्रतिमा बनवाने का मकसद नेहरू का अनादर करना नहीं: मोदी

अमरेली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल की भव्य प्रतिमा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ''अनादर करने'' के लिए नहीं बनाई गई है. पीएम मोदी ने यहां एक चुनावी रैली में कहा कि हालांकि कांग्रेस कहती है कि पटेल उनके नेता हैं, लेकिन पार्टी का कोई नेता अभी तक प्रतिमा देखने नहीं आया. मोदी ने अपने भाषण में कहा, ''जब आप गूगल पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा खोजते हैं, तब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गुजरात का नाम सामने आने पर क्या आपको गर्व महसूस नहीं होता.'' मोदी ने अधिकतर भाषण गुजराती में दिया. उन्होंने कहा, ''मैंने पंडित नेहरू का अनादर करने के लिए सरदार पटेल की प्रतिमा नहीं बनवाई. पटेल का कद इतना ऊंचा है कि आपको दूसरों को उनसे छोटा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है.'' मोदी ने नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप में सरदार पटेल को समर्पित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का पिछले साल 31 अक्टूबर को अनावरण किया था. 2,389 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने आतंकवाद को जम्मू-कश्मीर के केवल ''ढाई'' जिलों तक सीमित कर दिया है और देश के किसी अन्य हिस्से में पिछले पांच साल में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ. पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने गुजरात में जो कुछ सीखा, उससे उन्हें 2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध के दौरान मदद मिली. भारत ने चीनी बलों को डोकलाम में सड़क निर्माण से रोक दिया था जिसके बाद दोनों देशों के बलों के बीच 73 दिन गतिरोध की स्थिति बनी रही थी. मोदी ने कहा ''मेरे लिये यह चुनावी रैली नहीं है बल्कि यहां जो कुछ मैंने सीखा उसके लिए गुजरात के लोगों को धन्यवाद कहने की खातिर यह रैली है.'' देश में पहले हुईं बम विस्फोट की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ''देश के किसी अन्य हिस्से में पिछले पांच साल में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ. हमने आतंकवाद को जम्मू-कश्मीर के केवल ढाई जिलों तक सीमित कर दिया है.'' बालाकोट हवाई हमले के बाद भारत से संपर्क साधने की कोशिश संबंधी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर मोदी ने कहा कि नेता को ''फोन उठाने के लिए हमसे सार्वजनिक रूप से अनुरोध करना पड़ा''. उन्होंने देश में कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरदार सरोवर परियोजना 40 वर्ष पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी. मोदी ने कहा कि कांग्रेस को 2014 में आजादी के बाद सबसे कम सीटों पर जीत मिली और 2019 में वह सबसे कम लोकसभा सीटों पर लड़ रही है, लेकिन तब भी वह सत्तारूढ़ पार्टी बनने का ''सपना देख'' रही है।

गरीबी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है हमारी न्याय योजनाः राहुल गांधी

वंथली।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि देश के पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रूपये देने की उनकी पार्टी की न्याय योजना गरीबी पर एक वार तथा सर्जिकल स्ट्राइक है। श्री गांधी ने आज गुजरात के जूनागढ़ जिले के वंथली में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि इसको तुरंत चुनाव जीतने पर तुरंत लागू किया जायेगा। इसके जरिये गरीबी को समाप्त कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने तीन बड़े वायदे- दो करोड युवाओं को हर साल रोजगार देने, सबके खाते में 15 लाख रूपये डालने और किसानों को फसल की बेहतर कीमत दिलाने के बारे में किये थे। श्री गांधी ने कहा कि भले ही 15 लाख रूपये वाला वादा झूठा था पर उन्होंने कांग्रेस के अर्थशास्त्रियों और थिंक टैंक से पूछा था कि कितना पैसा देश के सबसे गरीब पांच करोड़ परिवारों को दिया जा सकता है तो उन्होंने यह रकम 72000 रूपये बतायी। यह मोदी सरकार की नोटबंदी और जीएसटी योजना जिनके चलते लोगों की जेब से पैसा निकल गया और खरीददारी वगैरह रूकने से फैक्टरियां बंद हो गयी, के उलट बंद अर्थव्यवस्था को चालू करने में मदद करेगा पैसा लोगों के खाते में डालने से वह खरीददारी शुरू करेंगे जिससे छोटे व्यवसायी ओर फैक्ट्रियों का कारोबार फिर से चल निकलेगा। इससे नौकरियां भी मिलेंगी। श्री गांधी ने दोहराया कि न्याय योजना तथा किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसे की उपलब्धता का सवाल खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 10 से 15 बड़े उद्योगपतियों का साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया पर किसानों का रिण माफ नहीं किया। कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फसल बीमा योजना से भी अनिल अंबानी और अन्य बड़े उद्योगपतियों को फायदा हुआ है। उनकी सरकार बनने पर किसानों के लिए अलग बजट बनाया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसानों को कर्ज अदायगी न करने के कारण जेल न जाना पड़े। श्री गांधी ने कहा कि एक तरफ अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे अरबपति बैंकों का बड़ा कर्ज पचा जाने के बावजूद जेल में नहीं है और लंदन में आनंद उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ 20 हजार रूपये जैसी छोटी रकमों के लिए किसानों को जेल में डाला जा रहा है। यह गलत है। या तो श्री मोदी पहले अनिल अंबानी को भी जेल में डाले या किसी को नहीं। कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को कर्ज के चलते जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद को चौकीदार कहने वाले श्री मोदी असल में अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों के चौकीदार हैं जिन्हे वह सारे संसाधन दे रहे हैं।

वह दो तरह का भारत बनाना चाहते हैं। एक 15 से 20 सबसे अमीरों के लिए आसानी से उपलब्ध सभी सुविधाओं वाला और दूसरा जिसमें आम आदमी के लिए बच्चों की पढ़ाई और इलाज भी बेहद महंगे हों। कांग्रेस दो भारत नहीं बनने देगी। श्री गांधी ने दोहराया कि श्री मोदी ने खुद पहल कर राफेल विमान सौदा अपने मित्र उद्योगपति अनिल अंबानी को दिलाया और उन्हें 30 हजार करोड़ का फायदा पहुंचाया।

किसानों की कर्जमाफी संबंधी घोषणा को लेकर लग सकती है पार्टियों पर रोक, न्यायालय में याचिका दायर

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर राजनीतिक दलों को उनके चुनाव घोषणापत्रों में कर्ज माफी और अन्य मौद्रिक योजनाओं की पेशकश करने से रोकने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन योजनाओं में सरकारी कोष का इस्तेमाल होता है और इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों को भी कर्ज माफी करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। साथ ही, बैंकों को गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डालने से रोके जाने की जरूरत है। यह याचिका अधिवक्ता रीना एन सिंह ने दायर की है। यह न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 22 अप्रैल को सुनवाई किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्यों को एक कृषि नीति बनानी चाहिए जो इस क्षेत्र को लाभप्रद बनाए और किसानों को समृद्ध बनाने में मदद करे तथा कृषि में उनकी रूचि बढ़ाए। याचिका में कहा गया है, ''राजनीतिक दलों को अपने चुनाव घोषणापत्रों में कर्ज माफी योजनाएं या अन्य मौद्रिक योजनाओं की पेशकश करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों को, चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में, वोटरों के एक बड़े तबके या वोटबैंक को लुभाने के लिए अपने राजनीतिक मकसद की खातिर सरकारी कोष का दुरूपयोग करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।याचिका में केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), चुनाव आयोग, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भी पक्ष बनाया गया है।

सुषमा की पार्टी कार्यकर्त्ताओं को सलाह- चुनाव युद्ध की तरह, सही तथ्यों के हथियार लेकर करें प्रचार

अहमदाबाद। विदेश मंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने चुनाव को युद्ध सरीखा करार देते हुए चुनावी योद्धा के तौर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्त्ताओं को 'सही जानकारी अथवा तथ्य तथा 'सबल तर्क के रूप में दो हथियार लेकर प्रचार करने की आज अपील की और दावा किया अपने काम के बल के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे। स्वराज ने यहां भाजपा के एक महिला सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि चुनाव युद्ध की तरह है और जैसे युद्ध में सैनिक सही हथियार लेकर निकलते हैं वैसे ही चुनावी योद्धाओं के पास दो हथियार सही तथ्य और सबल तर्क होने ही चाहिए। सारी चीजों की सही जानकारी और इसके ताकिर्क ढंग से लोगों के समक्ष रखने का माद्दा विरोधियों तक को अपने पक्ष में कर सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्त्ताओं को लोगों को तीन मुद्दों- राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और लोक कल्याण संबंधी सरकारी कामों के बारे में बताना चाहिए। सुषमा ने कहा कि मोदी सरकार ने उरी और पुलवामा हमले के बाद न केवल सर्जिकल और एरियल स्ट्राइक किए बल्कि पाकिस्तान को अलग थलग भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई में 2008 के 26 नवंबर को हुए देश के सबसे बड़े आतंकी हमले में मारे गए कुल 166 लोगों में से 40, अन्य 14 देशों के थे। उस समय की सरकार इन देशों को साथ लेकर पाकिस्तान को अलग थलग कर सकती थी पर उसने ऐसा नहीं। अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के संगठन में भी अलग थलग कर दिया। जब 57 इस्लामिक देशों के इस संगठन का 1969 में गठन हुआ था तब भारत के प्रतिनिधि के तौर पर तत्कालीन विदेश मंत्री फखरूद्दीन अली अहमद को पाकिस्तान की आपत्ति पर इसमें भाग लिये बिना लौटना पड़ा था ।

भाजपा कभी भी कश्मीर को देश से अलग नहीं होने देगीः शाह

रायगढ़।

भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए आज कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेताओं के द्वारा देश में दो प्रधानमंत्री की बात पर भले ही गांधी ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन भाजपा कभी भी कश्मीर को देश से अलग नहीं होने देगी। शाह आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित रामलीला मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और आतंकवादियों के प्रति अपना नरम रूख कर ले, किन्तु भाजपा का स्पष्ट मत है कि देश की सुरक्षा में खलल डालने वाले किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवादियों की इस करतूत पर करारा जवाब देकर अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दे दिया था। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश के लिए घुसपैठिए दीमक की तरह खतरनाक साबित हो रहे हैं। भाजपा की सरकार की वापसी के बाद इन घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर खदेड़ा जाएगा। शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने महज चार महीनों में ही राज्य के लोगों को कांग्रेस पार्टी का परिचय देना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बदलाव लाने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के शासन में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में भले ही कोई इंडस्ट्रीज नहीं ला पाई हो, लेकिन उन्होंने तबादला उद्योग का छत्तीसगढ़ में भलिभांति संचालन का काम शुरू कर दिया है।

राजनाथ सिंह बोले, भारत कांग्रेस मुक्त होने पर ही गरीबी से मुक्त होगा

अमता । केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबी मिटाने के वादे का उपहास उड़ाते हुए कहा कि भारत कांग्रेस मुक्त होने पर ही गरीबी से मुक्त हो पाएगा. हावड़ा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के दिनों से ही कांग्रेस गरीबी मिटाने का वादा कर रही है. उन्होंने कहा, ''अब, राहुल गांधी यह वादा कर रहे हैं. तथ्य यह है कि देश कांग्रेस मुक्त होने पर ही गरीबी से मुक्त होगा.'' पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में उसके शासन के अधीन लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया है. उन्होंने कहा, '' लोकतंत्र का बंगाल में कोई अस्तित्व नहीं है. उन्होंने कहा, '' लोकतंत्र का बंगाल में कोई अस्तित्व नहीं है. विपक्षी दलों के साथ जिस तरह हिंसा की जा रही है, क्या यह लोकतंत्र की निशानी है? बंगाल में हम लोकतंत्र बहाल होने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.'' तृणमूल कांग्रेस के ''मा, माटी और मानुष'' नारे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, तृणमूल के शासन में ''मां, मातृभूमि और लोग सभी पीड़ित हैं.''

पश्चिम दिल्ली से आप उम्मीदवार ने किया नामांकन, गठबंधन पर संशय बरकरार

नेशनल डेस्क।

दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आप के बीच चल रही गठबंधन की वार्ती किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती दिख रही है। माना जा रहा है दोनों पार्टियां अकेले चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी दिल्ली से आप उम्मीदवार बरवीर सिंह जाखड़ ने गुरुवार को अनपा दाखिल किया है। इस दौरान पार्टी नेता गोपाल राय उनके साथ मौजूद रहे। राय ने इससे पहले कांग्रेस पर डील से पलटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने अंतिम प्रयास किया और हमारे राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने बातचीत की, लेकिन मामले और सीट शेयरिंग को करीब-करीब सुलझाने के बाद पता नहीं क्यों कांग्रेस ने कदम पीछे खींच लिए। गौरतलब है कि दिल्ली में सात सीटों पर गठबंधन के लिए काफी दिनों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद दोनों पार्टियां किसी नतीजे पर पहुंच सकी। बताया जा रहा है कि आप जहां कांग्रेस के साथ दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी गठबंधन करना चाहती है तो वहीं कांग्रेस केवल दिल्ली में गठबंधन की इच्छुक है। बता दें कि कांग्रेस दिल्ली में आप को चार सीटें देने की पेशकश कर चुकी है। लेकिन वह अपनी शर्त पर बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक, आप का कहना है कि अगर दिल्ली में ही गठबंधन होगा तो 5-2 के फॉर्मूले पर होगा।

दिल्ली में आप व कांग्रेस गठबंधन तय, हरियाणा में इन सीटों को लेकर चल रही बात

नई दिल्ली ।

आम आदमी पार्टी-कांग्रेस के गठबंधन पर सस्पेंस जल्द ही खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में आप व कांग्रेस में 4-3 का फार्मूला तय कर लिया गया है। इसके साथ-साथ हरियाणा में गठबंधन के लिए दोनों दलों के बीच कई दौर की बैठकें हुई। कांग्रेस-आप गठबंधन में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) भी शामिल होगी। जेजेपी सोनीपत और कुरूक्षेत्र की दो सीट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद जेजेपी ने सिरसा और कुरूक्षेत्र की सीट देने की मांग की। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में फूट के बाद दुष्यंत चौटाला पर इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) से अलग होकर जेजेपी का गठन किया है। कुरुक्षेत्र की सीट देने के लिए कांग्रेस राजी है। सोनीपत या सिरसा को लेकर कांग्रेस विचार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत सीट नहीं देना चाहते हैं। आप-कांग्रेस गठबंधन को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बातचीत की। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको राहुल गांधी के आवास पर उनसे मिले। गौरतलब है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर कई महीनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले तो कांग्रेस में ही आप से गठबंधन को लेकर दो राय थी। शीला दीक्षित का खेमा गठबंधन का विरोध कर रहा था। वहीं अजय माकन और पीसी चाको इसके समर्थन में थे। जब पार्टी में करीब-करीब सहमति बनी तो आप ने हरियाणा और पंजाब में भी गठबंधन की शर्त रख दी। ध्यान रहे कि दिल्ली और हरियाणा में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली की सात और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में 2014 के चुनाव में बीजेपी ने सात, इनेलो ने दो और कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में सभी पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ी। 2014 के चुनाव में दिल्ली की सभी सात सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।

संपादकीय

टिक टॉक पर पाबंदी

हल्ला हालांकि पूरी दुनिया में है, लेकिन मोबाइल फोन के लिए वीडियो के सोशल मीडिया एप टिक टॉक की दुकान भारत में तो फिलहाल बंद हो गई है। चीन में तैयार यह एप पिछले कुछ समय में काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ था। खासकर नई पीढ़ी के नौजवानों में इसने बहुत तेजी से जगह बनाई थी। इससे पहले कि इसका नाम सुर्खियों में आता, भारत में इसके पांच करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हो गए थे। वैसे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में यही हाल था। अमेरिका में इस साल की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल एप टिक टॉक ही था। इसके अचानक ही लोकप्रिय हो जाने के कारण भी स्पष्ट हैं। यह ऐसा एप है, जिस पर बहुत छोटे वीडियो डाले और साझा किए जा सकते हैं, एक चौथाई मिनट से भी कम के। इसीलिए यह यू-ट्यूब से ज्यादा सुविधाजनक भी है। वहां वीडियो अपलोड करने में लंबा समय लगता है, जबकि टिक टॉक पर यही काम कुछ सेकंड में हो जाता है। शायद इसलिए नई पीढ़ी ने इसे हाथों-हाथ लिया। इसके साथ ही छोटे-छोटे वीडियो बनाने और इसके लिए कुछ भी कर गुजरने का पागलपन बढ़ा। इसके बहुत तेजी से प्रसार ने लोगों के कान तो पहले ही खड़े कर दिए थे, लेकिन जब इसमें अश्लील सामग्री और पोर्नोग्राफी की पकड़ बढ़ी, तो मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद केंद्र सरकार के आग्रह पर गूगल और एप्पल के प्ले स्टोर से इसे भारत के लिए हटा दिया गया, यानी अब इसे भारत में डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। हालांकि इस पूरे विवाद को चीन में अलग तरह से देखा जा रहा है। वहां धारणा यह है कि पूरे साइबर विश्व में अमेरिकी कंपनियों ने अपना दबदबा बना लिया है और अब जब चीन की कंपनियां उन्हें चुनौती देने में सफल हो रही हैं, तो उनके लिए बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। लेकिन यह भी सच है कि चीन की कंपनियों की साइबर गतिविधियां हमेशा से शक के दायरे में रही हैं। चीनी कंपनियों पर विभिन्न देशों के डाटा चुराने के आरोप नए नहीं हैं। चीनी दूरसंचार कंपनी हुवाई के खिलाफ अमेरिका ने जो कड़े कदम उठाए, उसके पीछे भी यही कारण माना जाता है। खुद भारत में भी यूसी ब्राउजर पर ऐसे ही कारणों से पाबंदी लगाने की बात उठी थी। आरोप था कि यह ब्राउजर उपयोगकर्ताओं के डाटा को चीन भेजता है। इससे अलग जहां तक पोर्नोग्राफी की बात है, तो वह इंटरनेट पर टिक टॉक से पहले भी थी, और उस पर पाबंदी लगाने के बाद भी पूरी तरह से खत्म होने वाली नहीं है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इंटरनेट में 30 फीसदी से ज्यादा सामग्री पोर्नोग्राफी है, जबकि कुछ अध्ययनों का कहना है कि ऐसी सामग्री 50 फीसदी से भी ज्यादा हो सकती है। साइकोलॉजी टुडे का एक अध्ययन बताता है कि दुनिया के 90 फीसदी लड़के और 60 फीसदी लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले ही ऐसी सामग्री के संपर्क में आ जाते हैं, जो सिर्फ वयस्कों के लिए ही होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें से ज्यादातर सामग्री में महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार भी दिखाया जाता है। जाहिर है, नई पीढ़ी को इस बुराई से दूर रखने का काम सिर्फ एक टिक टॉक पर पाबंदी से पूरा होने वाला नहीं है। इस समस्या को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंभीर प्रयास से ही खत्म किया जा सकता है।

उत्तर-पूर्व की नयी सुरक्षा चुनौतियां

जी. पार्थसारथी

देश के लोगों का मुख्य ध्यान ज्यादातर पश्चिमी सीमा पर बने तनाव और घटनाओं पर केंद्रित है, जिसका आगाज पुलवामा में हुए आतंकी हमले से हुआ था और इसके प्रतिकर्म में पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई कार्रवाई की गई थी। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक माहौल एकदम गर्मा गया था। इसी वक्त भारत में लोकसभा चुनाव प्रचार कटु राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच जारी है। चिंता की बात है कि हमारा पूरा ध्यान पश्चिमी सीमा पर केंद्रित है वहीं हम उन घटनाओं को अनदेखा कर रहे हैं जो हमारी पूर्वी थलीय और जलीय सीमाओं के पार से बन रही हैं। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की 5800 कि.मी. सीमा रेखा साझा है। यह असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इन राज्यों को सीमापारीय आतंकी एवं पृथकतावादी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सभी पृथकतावादी गुट तथाकथित 'यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ साउथ एशिया' के झंडे तले एकजुट हो गए हैं। इनमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन)-के, कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (असम) शामिल हैं। लगभग दस साल पहले इन सब को बांग्लादेश में बनाए गए अपने अड्डों को छोड़ना पड़ा था जब शेख हसीना ने सत्ता संभाली थी। उनकी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के आईएसआई के साथ नजदीकी संबंध थे और उन्होंने भारतीय पृथकतावादी गुटों को बांग्लादेश की भूमि से खुलकर काम करने की इजाजत दे रखी थी। इन लोगों के साथ बांग्लादेश के अतिवादी और आतंकी संगठन जैसे कि जमात-ए-इस्लामी और जमात-उल-मुजाहिदीन की भी मिलीभगत थी। ये गुट म्यांमार की धरती और साथ लगते चीन के युन्नान प्रांत में बनाए अड्डों से अपनी करतूतें जारी रखे हुए हैं। म्यांमार के पृथकतावादी गुटों को भी चीन सहायता और सुरक्षित ठिकाने मुहैया करवा रहा है। इनमें काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, अराकान आर्मी और यूनाइटेड वॉ स्टेट आर्मी का नाम शामिल है। चीन इन गुटों के साथ अपने संबंधों को म्यांमार की सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है, जिसके अंतर्गत वह चाहता है कि म्यांमार उसके द्वारा तजवीज किए गए आर्थिक और बुनियादी ढांचे विकसित करने संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी देने में सहयोग करे। तथापि म्यांमार की सेना ने हाल के महीनों में भारत विरोधी एनएससीएन (खपलांग) आतंकी गुट पर कड़ी कार्रवाई की है। म्यांमार की सेना ने इस किस्म के सख्त कदम उल्फा के खिलाफ भी उठाए हैं और इसके बड़े नेता ज्योतिर्मोय असोम को मार गिराया है। इसी प्रकार भारत के साथ लगते म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र में अपने ठिकाने बनाने वाली एनएससीएन (के) के सशस्त्र सदस्यों को भी सीमा से दूर धकेल कर कैंपों में सीमित कर दिया गया है। म्यांमार आतंकवाद के विषय पर भारत के साथ काफी सहयोग कर रहा है, जिससे नागालैंड में शांति बनाने की भारतीय कोशिशों को बल मिला है। म्यांमार के राखिने प्रांत में बसे रोहिंग्या मुसलमानों पर सेना द्वारा की गई कार्रवाई में लगभग 11 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश भागने को मजबूर हुए हैं। रोहिंग्याओं ने इंडोनेशिया और भारत में भी शरण ली है। चीन और जापान ने इन शरणार्थियों की अपनी मातृभूमि तक फिर से पहुंचाने और बसाने हेतु खासी रकम से सहायता करने की घोषणा की है। अलबत्ता इस विषय को न तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने रखा गया और न ही म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की कोई तजवीज आई है, हालांकि ऐसा होने की स्थिति में चीन और रूस द्वारा वीटो किए जाने की पूरी उम्मीद थी। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की लगातार उपस्थिति से यह खतरा है कि कहीं ऐसा न हो कि कट्टरवादी इस्लामिक गुट पाकिस्तानी शह पर इनका शोषण अपने मंतव्य की पूर्ति के लिए कर लें ताकि शेख हसीना की सरकार को अस्थिर किया जा सके। ऐसा होने पर भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में शांति और सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना बन जाएगी।

भारत के साथ लगती म्यांमार की पश्चिमी सीमा के समूचे क्षेत्र में 'अराकान आर्मी' के सैकड़ों विद्रोहियों से दरपेश नई चुनौतियां बनने लगी हैं। ये पृथकतावादी म्यांमार की सीमा से लगे मिजोरम और मणिपुर के इलाकों में गतिविधियां चला रहे हैं। भारत और म्यांमार की सेना मिलकर इस नई चुनौती से निपटने का उपाय कर रही हैं। यह इलाका भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सामरिक महत्व का 'कलादान गलियारा' जिससे माध्यम से बंगाल के खाड़ी के तट पर म्यांमार के सित्वे बंदरगाह को भारत के तटविहीन उत्तर-पूर्वी राज्यों को सीधे जोड़ने की परियोजना निर्माणाधीन है, वह कॉरीडोर इसी क्षेत्र से गुजरता है। यह गलियारा शेष भारत से उत्तर-पूर्वी राज्यों तक वस्तुएं लाने-ले जाने की सुविधा प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने के अतिरिक्त सिलीगुड़ी से रेल मार्ग में व्यवधान आने की सूरत में इन राज्यों तक हमारी पहुंच लगातार बनाए रखने में सहायक होगा। इसी बीच चीन भी अपने तटविहीन युन्नान प्रांत को समुद्री तट से जोड़ने हेतु म्यांमार से होकर गुजरने वाला नेटवर्क बना रहा है, जिसके तहत बंगाल की खाड़ी के तट पर म्यांमार के बंदरगाह क्याकप्यू से युन्नान तक सड़क-रेलमार्ग और ऊर्जा संयंत्र बनाए जा रहे हैं। क्याकप्यू बंदरगाह भारत की मदद से विकसित किए जा रहे सित्वे बंदरगाह से ज्यादा दूरी पर नहीं है। माना जा रहा है कि चीन द्वारा बनाया जा रहा 'सड़क और ऊर्जा गलियारा' म्यांमार का शोषण करने वाला सिद्ध होगा। इसके अलावा मईत्सोने बांध की मार्फत बनने वाली विशाल पनबिजली परियोजना के खिलाफ स्थानीय नागरिकों ने भारी प्रदर्शन किया है। इस बांध से बनने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा म्यांमार की बजाय चीन के इस्तेमाल के लिए होगा। पिछले दिनों में ऐसे मौके रहे हैं जब अराकान आर्मी, जिसके रिश्ते काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के माध्यम से चीन से साथ नजदीकी हैं, उसने कलादान कॉरीडोर बनाने के काम में लगे म्यांमार के मजदूरों पर हमला किया है। हमारी उत्तर-पूर्वी राज्यों की सीमा से लेकर बंगाल की खाड़ी के तट तक पसरे इलाके की क्षेत्रीय स्थिरता को बांग्लादेश के अंदर उपजने वाले तनावों से गंभीर खतरा होगा। अगर रोहिंग्याओं को पुनः अपनी मातृभूमि पर बसाने की समस्या का हल जल्द न निकाला गया तो इसके नतीजे में पैदा होने वाला रोष बांग्लादेश के अंदर मौजूद कट्टरवादी इस्लामिक गुटों को उभारने का सबब बनेगा। जहां अमेरिका और इसके यूरोपियन सहयोगी देश रोहिंग्या शरणार्थियों की आर्थिक मदद कर रहे हैं वहीं म्यांमार की कड़ी आलोचना करना रोहिंग्याओं की वापसी पर उसके द्वारा रुख कड़ा करने का सबब बनी है। भारत को इस प्रक्रिया में तंत्र बनाने के लिए चीन, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया और अन्य पड़ोसी आसियान संगठन के देशों को साथ मिलाना होगा ताकि रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी अपने वतन म्यांमार को जल्द करना सुनिश्चित बनाया जा सके। रोहिंग्या शरणार्थियों के रोष को भुनाने की ताक में बैठे लोगों को इस क्षेत्र की स्थिरता को बिगाड़ने का मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे न केवल बांग्लादेश और म्यांमार बल्कि बंगाल की खाड़ी के साथ लगते सभी देश प्रभावित होंगे।

लेखक पूर्व राजनयिक हैं।

ट्वीट

मुद्दा

चूंकि मोदीजी कहते हैं कि जवानों की शहादत एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए, तो क्यों नहीं वो कश्मीर में जवानों और नागरिकों की शहादत के इन आंकड़ों की सफाई देते? मोदीजी की सरकार के दौरान दोनों आंकड़े क्यों बढ़े? या की अब इसे चुनावी मुद्दा बनाना देशद्रोह हो जाएगा?

योगेन्द्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष-स्वराज इंडिया

ज्ञान गंगा

परमात्म तत्त्व

श्री राम शर्मा आचार्य

मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, उसका संबंध परमात्म तत्त्व से स्पष्ट और प्रकट हो जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति उच्च शक्तियों के रूप में होकर संसार को प्रभावित करने लगती है और लोग उस व्यक्ति को अवतार, ऋषि, योगी आदि के रूप में पूजने और मनन करने लगते हैं। वह दिव्य पुरु ष बन जाता है। परमात्म तत्त्व वह अनंत जीवन, वह सर्वव्यापी चैतन्य और वह सवरेपरि सत्ता है, जो इस जगत के पीछे अदृश्य रूप से काम करती, इसका नियमन और नियंत्रणकरती है और जिससे दृश्यमान जीवन आता है और सदा सर्वदा आता रहेगा। इसी अनंत, असीम और अनादि ज्ञान और शक्ति के भंडार से संबंध स्थापित हो जाने से साधारण मनुष्य असाधारण बनकर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता हो जाता है। अणु-अणु का मूलाधार वह परमात्म तत्त्व ही है। आकार-प्रकार में भिन्न दिखते हुए भी प्रत्येक पदार्थ एवं प्राणी एक उसी तत्त्व का अंश है। जिस प्रकार समुद्र से उठाया हुआ एक जल बिन्दु भिन्न दिखता हुआ भी मूलतः उसी का संक्षिप्त स्वरूप होता है और समुद्र की सारी विशेषताएं उसमें होती हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन और समष्टिगत जीवन सीमित और असीमित के मिया के भेद के साथ तत्त्वतः एक ही है। जो जीवात्मा है, वही परमात्मा और जो परमात्मा है वही जीवात्मा। इस सत्य को जानना ही आत्म ज्ञान है। जिन-जिन महापुरु षों ने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली है, उन्होंने अपना अनुभव प्रकट करते हुए उसकी इस प्रकार पुष्टि की है कि हम अपना जीवन परमात्म तत्त्व से एक दिव्य प्रवाह के रूप में पाते हैं अथवा हमारे जीवन का उस परमात्म तत्व से ऐक्य है। हममें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। हम और हमारा ईर एक सत्य के ही दो नाम और दो रूप हैं। यही ज्ञान अथवा अनुभव आत्मानुभूति आत्म प्रतीति अथवा आत्म ज्ञान के अर्थ में मानी गई है। प्रतीति के साथ शक्ति का अटूट संबंध है, जिसे अपने प्रति सर्वशक्तिमान की प्रतीति होती है। वह सर्वशक्तिमान और जिसको अपने प्रति निर्बलता की प्रतीति होती है वह निर्बल बन जाता है और तदनुसार उसका जीवन व्यक्त अथवा प्रकट होता है। अपने प्रति इस प्रतीति की स्थापना करने का प्रयास ही आत्म ज्ञान की ओर अग्रसर होना है।

सवालों के घेरे में श्रम सुधार

मुद्दा/भारत डोगरा

हाल के समय में अनेक श्रमिक व श्रमिक संगठन अनेक सवालों व समस्याओं से घिरे रहे हैं। जहां एक ओर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अधिक बेरोजगारी झेलनी पड़ी है, वहां दूसरी ओर संगठित क्षेत्र में भी स्थाई मजदूरों के स्थान पर ठेका मजदूरों का प्रतिशत बढ़ने से इस क्षेत्र में भी परेशानी है। उद्योगों के वार्षिक सव्रेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि उद्योगों में उत्पादकता बढ़ने के बावजूद कामगारों के लाभ में कम वृद्धि हुई है। 1980 के दशक के आरंभिक दौर में मजदूरी का हिस्सा 30 प्रतिशत था व मुनाफे का हिस्सा 20 प्रतिशत था, 1990 के दशक के बाद में यह हिस्से बदल गए। हाल के समय में नेट मूल्य वृद्धि में मुनाफे का हिस्सा 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया व वर्ष 2007-08 में अपने चरम पर पहुंचते हुए 60 प्रतिशत का आंकड़ा भी पार कर गया। वित्तीय संकट के बाद यह कुछ कम होने पर भी संगठित उद्योग (मैनुफैक्चिरिंग) में यह नेट मूल्य वृद्धि के 50 प्रतिशत से अधिक बना रहा है। इसी समय के दौरान मूल्य वृद्धि में मजदूरी का हिस्सा कम होकर 10 प्रतिशत हो गया व हाल के वर्षो में इसके आसपास ही बना रहा है। इस शताब्दी के आरंभ से रोजगार प्राप्त कर रहे मजदूरों में ठेका मजदूरों का हिस्सा 20 प्रतिशत से कम था, पर एक दशक में यह एक-तिहाई से भी अधिक हो गया। ठेका मजदूरों की कार्य अवधि असुरक्षित होती है, उन्हें कम मजदूरी मिलती है व उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ नहीं मिलते हैं। संगठित क्षेत्र में 1980 के दशक में कामगारों की मजदूरी व प्रबंधकों के वेतन एक साथ बढ़ रहे थे, 1990 के दशक के आरंभिक दौर से उनकी दूरी बढ़ने लगी व यह तब से बढ़ती ही रही है। इसके नवीनतम आंकड़े वर्ष 2012 तक उपलब्ध हैं। इस वर्ष तक प्रबंधकों के वेतन 10 गुणा से भी अधिक बढ़ गए पर कामगारों की मजदूरी 4 गुणा से भी कम बढ़ी। भारत के आर्थिक सव्रेक्षण 2017 में स्वीकार किया गया, भारत अपनी बढ़ती हुई श्रम शक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बहुत कम रोजगार का सृजन कर पाता है, व इस कारण अनेक व्यक्ति कामगार शक्ति से बाहर रह जाते हैं, अनेकों को अर्ध या अल्प रोजगार मिलता है व अनेक को बहुत कम मजदूरी या आय मिलती है। श्रम-सुधारों के नाम पर लगभग 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम कोड में एकत्र किया जा रहा है। इन कोड का हाल में श्रमिक मामलों के जानकार ने अध्ययन किया है। उनका निष्कर्ष है कि हालांकि यह श्रम कानूनों को सरलीकृत व सुगठित करने के नाम पर किया जा रहा है, पर इसके बारे में अनेक सवाल उठते रहते हैं कि इससे मजदूरों के अनेक वर्षो के संघर्षो से प्राप्त किए गए अधिकार कम हो सकते हैं व श्रम संगठन/ट्रेड यूनियन पहले से कमजोर पड़ सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी अंतिम फैसला बाकी है और अभी चार श्रम कोड के प्रारूप ही उपलब्ध हैं, अंतिम कानून नहीं बना है। फिर भी इन कोड के प्रारूप पर जो चर्चा अभी तक हुई है, उसमें श्रमिकों और श्रमिक संगठनों की कई गंभीर शंकाएं सामने आई हैं। हकीकत यह रही है कि जब मजदूर समर्थक कानून मौजूद होते हैं तब भी शक्ति संतुलन देखते हुए मजदूरों के लिए न्याय प्राप्त करना प्रायः बहुत कठिन होता है। तिस पर यदि कानूनों को ही कमजोर कर दिया जाए तो मजदूरों के लिए न्याय प्राप्त करना और कठिन हो जाएगा। एक अन्य समस्या यह खड़ी है कि अनेक श्रम कानूनों का दायरा पहले से कम कर दिया गया है, जिससे बहुत कम मजदूर उसके दायरे में आते हैं। प्रस्तावित कोड जिस दिशा में जा रहे हैं, उसी तरह के कुछ संशोधन भी श्रम कानूनों में होने लगे हैं। बहुत संघर्ष के बाद संगठित क्षेत्र के कुछ मजदूरों जैसे कि निर्माण मजदूरों व रेहड़ी-पटरी वालों के लिए जो कानून बनाए गए थे, उनका क्रियान्वयन भी अभी तक ठीक से नहीं हो सका है। इन कानूनों में जो संभावनाएं निहित थीं, उसका बहुत कम लाभ ही इन मेहनतकशों को मिल सका है। इतना ही नहीं, निर्माण मजदूरों के कानून के लिए कुछ नई अनिश्चित स्थितियां भी उत्पन्न हो गई हैं। इसके अतिरिक्त विमुद्रीकरण जैसे फैसलों से भी श्रमिक वर्ग को बहुत क्षति उठानी पड़ी है। इन सब स्थितियों को देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि चुनाव बाद जिसकी भी सरकार बने वह श्रमिकों की समस्याओं व सवालों को सुलझाने पर सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाए। जो भी प्रस्तावित श्रम सुधार है, वे वास्तव में मजदूरों की बेहतरी के लिए होने चाहिए। शक्ति संतुलन तो वैसे ही मजदूरों के विरुद्ध है, कम-से-कम कानून का सहारा मजदूरों को मिलना चाहिए।

आज का राशिफल

मेष बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें।

वृषभ सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। वाणी की सौम्यता आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। धन लाभ के योग हैं।

मिथुन जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। किसी मित्र या रिश्तेदार से धन लाभ के योग हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे।

कर्क संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

सिंह पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शासन सत्ता से तनाव मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कन्या आर्थिक योजना फलीभूत होगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। भारी व्यय की संभावना है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।

तुला जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे।

वृश्चिक बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। वाद-विवाद की स्थिति आपके लिए हितकर नहीं होगी।

धनु व्यावसायिक योजना सफल होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। वाद विवाद की स्थिति आपके लिए हितकर नहीं होगी।

मकर पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। अनावश्यक व्यय हो सकता है।

कुम्भ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी।

मीन रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जनों से पीड़ा मिलेगी। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे।

कोटक महिंद्रा बैंक ने बीआईएलटी ग्राफिक के खिलाफ एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया

मुबंई (एजेंसी)।

कोटक महिंद्रा बैंक ने बल्लारपुर लिमिटेड(बीएलआईटी) के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास मामला दर्ज किया है। बैंक का कहना है कि बीएलआईटी ने बैंक के साथ 218 करोड़ रुपए का बैंकरप्सी की है। ग्राफिक पेपर उत्पादन करने वाली यह कंपनी पर अपने कर्जदाताओं का लगभग 6,000 करोड़ रुपये बकाया है। भारतीय रिजर्व बैंक की कथित दूसरी सूची में बीआईएलटी ग्राफिक पेपर का नाम 29 डिफॉल्टर कंपनियों में है। आरबीआई ने कहा था कि इन फर्मों को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के माध्यम से रिज़ॉल्यूशन के लिए भेजा जाएगा। वीसी सिंह और रविकुमार दुरीसामी की अध्यक्षता वाली कंपनी में एनसीएलटी द्वारा मुंबई आईबीसी के तहत कंपनी के प्रवेश को 5 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ-साथ बीआईएसटी ग्राफिक पर ईमेल क्रेरीज़ को प्रेस जाने के समय तक अनुत्तरित किया गया था। यह बीआईएलटी ग्राफक पेपर के खिलाफ दायर की गई दूसरी दिवाला याचिका है। इससे पहले फरवरी वर्ष 2018 में आईडीबीआई ने एनसीएलटी से संपर्क किया था। इसके बाद आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को निर्देश दिया था कि वह अपने कर्ज की पुनर्खरीद के पैकेज को अस्वीकार करने के बाद दिवाला अदालत में बीआईएलटी ग्राफिक का उल्लेख कर सकती है। क्योंकि केवल 70 प्रतिशत ऋणदाताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन मार्च 2018 में कंपनी ने आरबीआई के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी थी।

फेसबुक ने अंजाने में अपलोड कीं 15 लाख यूजर्स की ईमेल आईडी

बिजनेस डेस्क (एजेंसी)।

फेसबुक इंक की एक रिपोर्ट में खुलासा करते हुआ कहा है कि ऐसा हो सकता है कंपनी ने अंजाने में मई, 2016 के बाद करीब 15 लाख यूजर्स की ईमेल आईडी को अपलोड कर दिया है। ये सोशल मीडिया कंपनी के सामने निजता को लेकर एक नई समस्या बन सकती है। इससे पहले मार्च में कंपनी ने कहा था कि फेसबुक ने एक विकल्प के तौर पर पहली बार साइनअप करने वाले यूजर्स को ईमेल पासवर्ट वेरिफिकेशन को पेश करना बंद कर दिया था। फेसबुक को हाल ही में निजता से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिसमें ये खबर भी थी कि लाखों यूजर्स के पासवर्ड रीडेबल फॉर्मेट में उसके कर्मियों के इंटरनल सिस्टम में संग्रहित हैं। बीते साल लंदन की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म कैंब्रिज एनालिटिका द्वारा फेसबुक के डाटा लीक के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। इसके बाद कई जांच हुईं और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसके लिए माफी भी मांगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने राइटर्स से कहा है, हमारा अनुमान है कि शायद 15 लाख लोगों के ईमेल कॉन्टैक्ट्स अपलोड हो गए हैं। ये कॉन्टैक्ट्स किसी के साथ शेयर नहीं किए गए हैं और हम उन्हें डिलीट कर रहे हैं। कंपनी ने कहा था कि ऐसे मामले सामने आए थे कि जब लोगों ने फेसबुक पर अकाउंट बनाया तो उनके ईमेल कॉन्टैक्ट्स अपलोड होने लगे।

फेसबुक ने ये भी कहा कि जिन यूजर्स के कॉन्टैक्ट अपलोड हुए हैं, उन्हें इस बात की जानकारी दे दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि गड़बड़ी को ठीक कर लिया गया है।

गूगल ने एक बार फिर डूडल बनाकर मतदाताओं को किया प्रेरित

नई दिल्ली (एजेंसी)।

देश में गुरुवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और सर्च इंजन गूगल ने इस अवसर पर एक बार फिर डूडल बनाकर मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया है। दूसरे चरण में देशभर की 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। चुनाव को लेकर मतदाताओं में जहां एक ओर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, वहीं गूगल ने भी अपने डूडल के जरिये लोगों को मतदान के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया है और संदेश दिया है कि लोकतंत्र में मतदान का कितना महत्व होता है तथा लोग कैसे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले चरण के चुनाव के दौरान भी गूगल ने डूडल बनाकर लोगों को मतदान का महत्व और तरीका समझाया था और अब एक बार फिर गूगल ने दूसरे चरण के चुनाव के दौरान वही डूडल बनाया है। गूगल ने डूडल बनाकर लोगों से मतदान यानी वोट करने की अपील की है। इस डूडल में उंगली पर स्याही लगी दिखाई दे रही है जिस पर क्लिक करते ही यूजर्स को 'हाउ टू वोट इंडिया' का पेज खुल रहा है। इस पेज पर मतदान की पूरी प्रक्रिया समझायी गयी है। गूगल ने अपने डूडल में उंगुली पर लगी जो नीली से याही दर्शायी है, वह भारत में मतदान के बाद मतदाताओं को लगायी जाती है। यह से याही आम तौर पर मतदाताओं की तर्जनी अंगुली पर लगाई जाती है, ।

हुंदई की कॉम्पैक्ट एसयूवी सेग्मेंट में बढ़त पर निगाहः किम

मुंबई (एजेंसी)।

हुंदई मोटर इंडिया का लक्ष्य अपने नए उत्पाद वेन्यू के जरिये देश में कॉम्पैक्ट एसयूवी वर्ग में बढ़त हासिल करने का है. कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही है. हालांकि कंपनी के लिए यह आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि उसे मारुति सुजुकी की विटारा ब्रिजा, टाटा मोटर्स की नेक्सन, महिंद्रा की एक्सयूवी300 और होंडा की डब्ल्यूआर-वी से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है. इन मॉडलों की कीमत 6.48 लाख रुपये से 11.99 लाख रुपये के बीच है. फिलहाल में 13 हजार से 14 हजार यूनिट प्रतिमाह की बिक्री के हिसाब से विटारा ब्रिजा इन सभी मॉडलों से सबसे आगे है. हुंदई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एसएस किम ने कहा, हम वेन्यू के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी श्रेणी में बढ़त हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी बाजार में सबसे आगे रहना चाहती है लेकिन साथ ही ग्राहकों को अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध कराना चाहती है. किम ने कहा कि वेन्यू पेट्रोल और डीजल दोनों तरह की इंजनों के साथ आएगी।

संक्षिप्त समाचार

9 शहरों में जनवरी-मार्च के दौरान कार्यालय स्थल की आपूर्ति 46 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। शीर्ष नौ शहरों में इस साल जनवरी-मार्च के बीच कार्यालय स्थल की आपूर्ति 46 प्रतिशत बढ़कर 1.34 करोड़ वर्ग फुट हो गयी। सीबीआरआई की एक रपट में ये आंकड़े दिये गए हैं। दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद एवं कोच्चि में 2018 के जनवरी से मार्च के बीच कार्यालय स्थल की आपूर्ति 92 लाख वर्ग फुट रही थी। आलोच्य अवधि के दौरान कार्यालय स्थल की आपूर्ति में सबसे अधिक वृद्धि हैदराबाद में दर्ज की गयी। शहर में यह आंकड़ा पिछले साल सात लाख वर्ग फुट का था, जो इस साल बढ़कर 52 लाख वर्ग फुट का हो गया। हैदराबाद में मांग बढ़ने के कारण आपूर्ति में यह बढ़ोतरी देखने को मिली है।

ब्रिटेन की अदालत द्वारा माल्या का भारतीय बैंकों से बकाया वसूली संबंधित अर्जी खारिज

लंदन। बुधवार को शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। माल्या ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने लंदन में बैंक के अपने एक खाते में जमा धन से संबंधित आदेश को निरस्त करने की अर्जी दी थी। जिसको उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम तौर पर अस्वीकार कर दिया है। अदालत के इस निर्णय से भारतीय बैंकों के समूह को जमा 2,60,000 पाउंड की राशि से वसूली करने से रोकने का माल्य का प्रयास विफल हो गया है। माल्या ब्रिटेन में कई कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। उच्च न्यायालय के मास्टर डेविड कुक ने व्यवस्था दी है कि एसबीआई और अन्य बैंकों के पक्ष में जारी अंतरिम ऋण आदेश पर कायम रहेगा। इससे भारतीय बैंक माल्या के आईसीआईसीआई यूके में इस खाते पर हाथ रख सकेंगे। लेकिन, इस अपील पर अंतिम आदेश माल्या की लंबित दिवाला याचिका पर सुनवाई के बाद दिया जाएगा। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय का कहना है कि खातों में जमा राशि फ्रीज रहेगी। पिछले साल भारतीय बैंकों के पक्ष में वैश्विक स्तर पर खातों को फ्रीज और उन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। माल्या के वकीलों ने कई कारण बताते हुए इस अंतरिम आदेश को रद्द करने की अपील की थी। उन्होंने ने कहा है कि माल्या को उचित तरीके से जीवनयापक के खर्च से रोकने का जानबूझकर प्रयास किया गया है।

लघु उद्यमियों को बड़ी राहत बिल डिस्काउंटिक सुविधा देगी:बैंक आफ महाराष्ट्र

नई दिल्ली। बुधवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लघु उद्यमियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। बैंक ने एमएसएमई इकाइयों के बकाया व्यापारिक बिलों के आधार पर कर्ज देने (डिस्काउंटिंग) के लिए एम-वन एक्सचेंज ट्रेड्स प्लेटफार्म के साथ साझीदारी की है। लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का समर्थन करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जहां कई पंजीकृत वित्तपोषक कंपनियां भाग ले सकती हैं। बैंक आफ महाराष्ट्र (बीओएम) का कहना है कि कि रिसीवेबल एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) एवं इन्वॉयसमार्ट के टीआरईडीएस के अलावा बैंक को अब माइंड सोल्यूसन्स के एम-वन एक्सचेंज मंच पर भी वित्तपोषक कंपनी के रूप में जोड़ा गया है। माइंड साल्युसन्स एक प्रौद्योगिकी प्रबंधन कंपनी है। जोकि एम-वन एक्सचेंज का ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म संचालित करती है। ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में नकदी के सुचारू प्रवाह को सुगम बनाना तथा प्रतिस्पर्धी दर पर वित्तपोषण उपलब्ध कराना है।

यूनाइटेड बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, ब्याज दर में कटौती की

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने अलग-अलग समयावधि के लिए दिये जाने वाले कर्ज पर कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर में 0.05 प्रतिशत की कटौती कींक की नई दरें गुरुवार (18 अप्रैल) से लागू होंगी. बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि बैंक की परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन समिति ने अपनी बैठक में बैंक की अवधि आधारित एमसीएलआर में संशोधन किया है. बैंक ने एक साल के कर्ज पर कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर को 8.85 प्रतिशत से घटाकर 8.80 प्रतिशत कर दिया है. इसी प्रकार, छह महीने और तीन महीने के कर्ज पर एमसीएलआर को घटाकर क्रमशः 8.60 प्रतिशत और 8.50 प्रतिशत किया गया है. वहीं, एक महीने और एक दिन के कर्ज पर भी एमसीएलआर में 0.05 प्रतिशत की कटौती की गई है. बैंक हर महीने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) की समीक्षा करते हैं।

सोना वर्ष के निचले स्तर पर-चांदी भी कमजोर,

बिजनेस डेस्क। विदेशों में पीली धातु के साल के निचले स्तर तक उतरने के कारण दिल्ली सरराफा बाजार में गुरुवार को सोना 385 रुपए लुढ़ककर वर्ष के निचले स्तर 32,385 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गया। चांदी भी 105 रुपये टूटकर 38,245 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बिकी। विदेशी बाजारों में मंगलवार दोपहर बाद सोने में रही बड़ी गिरावट का असर स्थानीय बाजार में आज देखा गया। बुधवार को महावीर जयंती के अवकाश के कारण दिल्ली सरराफा बाजार बंद रहा था। लंदन से मिली जानकारी के अनुसार, सोना हाजिर आज वहां एक समय 1,270.99 डॉलर प्रति औंस तक उतर गया जो 27 दिसंबर 2018 के बाद का इसका निचला स्तर है हालाँकि, बाद में कुछ सुधरता हुआ यह 0.85 डॉलर की बढ़त में 1,274.85 डॉलर प्रति औंस पर रहा। जून का अमेरिकी सोना वायदा भी 0.20 डॉलर की मजबूती के साथ 1,277 डॉलर प्रति औंस बोला गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों से निवेशकों ने सोने को छोड़कर शेयरों में पैसा लगाया है। इससे पीली धातु का भाव टूटा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी हाजिर भी 0.02 डॉलर चढ़कर 14.98 डॉलर प्रति औंस पर पहुँच गई।

आर.आई.एल. पर बड़ा दाव लगाएगी सऊदी अरामको, रिफाइनिंग बिजनैस की खरीद सकती है हिस्सेदारी

बिजनेस डेस्क (एजेंसी)।

दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरामको। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बड़ा दाव लगाने की तैयारी में है। दरअसल सऊदी अरब सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी आर.आई.एल. के रिफाइनिंग और पैट्रोकैमिकल्स बिजनैस में 25 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 'गंभीर बातचीत' कर रही है। आर.आई.एल. के रिफाइनिंग और पैट्रोकैमिकल्स बिजनैस की वैल्युएशन लगभग 55 से 60 अरब डॉलर है। इस हिसाब से माइनोरिटी स्टेक की बिक्री से मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी को 10 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर (70 हजार करोड़ से 1.05 लाख करोड़ रुपए के बीच) तक मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैल्युएशन को लेकर इस साल जून तक कोई एग्रीमैंट हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित डील को लेकर सलाह देने का काम गोल्डमैन साक्स को सौंपा गया है। मंगलवार के शेयर प्राइस के हिसाब से आर.आई.एल. की कुल मार्कीट कैप 8.5 लाख करोड़ रुपए थी। वित्तीय क्षेत्र के एक जानकार ने कहा कि आर.आई.एल. ने एनर्जा से लेकर रिटेल और रिटेल से लेकर टैलीकॉम तक खासा काम किया है। इस डील से यह फंड बढ़ाने में मदद मिलेगी और शेयर होल्डर को भी खासा फायदा होगा। आर.आई.एल. ने टैलीकॉम क्षेत्र में रिलायंस जियो में खासा निवेश किया है जिससे उस पर कुल कर्ज 3 लाख करोड़ हो गया है। कर्ज कम करने की प्रक्रिया से जियो को विस्तार की योजना पर काम करने का मौका मिलेगा।

किंगफिशर के बाद बंद होने वाली दूसरी देसी एयरलाइन बनी जेट एयलाइन

बिजनेस डैस्क (एजेंसी)।

पिछले एक दशक में किंगफिशर के बाद कामकाज बंद करने वाली जेट दूसरी कंपनी बन गई है। विजय माल्या की किंगफिशर ने साल 2012 में कामकाज बंद किया था। अब 26 साल से अपनी सेवाएं दे रही जेट एयरवेज ने अपनी उड़ाने रोक दीं। एक दिन में 650 फ्लाइट्स तक का परिचालन करने वाली देसी एयलाइन कंपनी जेट यह हालत बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने के कारण हुई। हालांकि, नरेश गोयल द्वारा स्थापित जेट एयरवेज के फिर से उड़ने की उम्मीद बची हुई है। नरेश गोयल ने 1991 में एयर टैक्सी के रूप में जेट एयरवेज की शुरुआत की थी। तब भारत में बिल्कुल संगठित तरीके से प्राइवेट एयरलाइंस के संचालन की अनुमति नहीं थी, जिसके एयरक्राफ्ट टाइम टेबल के मुताबिक उड़ान भरे, जैसा कि अब हो रहा है। एक साल बाद अपनी जेट ने चार जहाजों का एक बेड़ा बना लिया और जेट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान शुरू हो गई। 5 मई, 1993 को ही मुंबई-अहमदाबाद के लिए जेट की पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। भारतीय स्टेट बैंक (सीबीआई) के नेतृत्व में 26 ऋणदाताओं के एक संघ ने संभावित निवेशकों से बोलियां मंगाई हैं। बैंकों के समूह द्वारा 400 करोड़ रुपये की त्वरित ऋण सहायता उपलब्ध कराने से इनकार किए जाने के बाद एयरलाइन ने घोषणा की वह गुरुवार से उसकी सभी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहेंगी। ये परिचालन अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इसके लिए कंपनी ने नकदी की कमी का हवाला दिया। हालांकि, आज बृहस्पतिवार को जेट एयरवेज के ऋणदाताओं ने हिस्सेदारी की बिक्री के लिए बोली प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरी होने की उम्मीद जाहिर की। नकदी संकट से जूझ रहे एयरलाइन के अपनी सेवाओं को निलंबित करने के बाद कर्ज देने वालों ने ये आशा प्रकट की है। इससे जेट को लेकर थोड़ी उम्मीदें अभी भी हैं। जेट एयरवेज के परिचालन बंद करने के फैसले से जहां यात्रियों, एयरलाइन के आपूर्तिकर्ताओं का करोड़ों रुपया फंस गया और इसके 20 हजार से अधिक कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। एयरलाइन पर बैंकों का 8,500 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है जिसके चलते वह कर्ज संकट में फंसती चली गई। नरेश गोयल द्वारा शुरू की गई जेट एयरवेज ने ढाई दशक तक लाखों यात्रियों को विमान सेवायें उपलब्ध कराई लेकिन 2010 के संकट के बाद एयरलाइन का कर्ज संकट गहराने लगा। कंपनी को लगातार चार तिमाहियों में घाटा उठाना पड़ा। इसके बाद वह कर्ज के भुगतान में असफल होने लगी। पिछले साल दिसंबर में 123 विमानों के साथ परिचालन करने वाली कंपनी की अब एक भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर रही है।

जेट एयरवेज के पायलटों के संगठन नेशनल एविएटर्स गिल्ड के उपाध्यक्ष आदिम वालियानी ने कंपनी का परिचालन जारी रखने के लिये भारतीय स्टेट बैंक से 1,500 करोड़ रुपये जारी करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भी अपील करते हुए कहा कि वे कंपनी में काम कर रहे 20 हजार लोगों की नौकरियां बचायें।

जिओ ने बनाया एक और रिकॉर्ड, इस मामले में जापान और नीदरलैंड को भी पछाड़ा

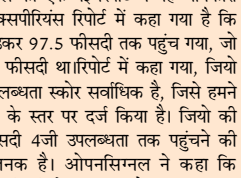

नई दिल्ली । दुनिया में किसी भी अन्य ऑपरेटर ने 4 जी उपलब्धता के मामले में भारत में रिलायंस जियो की तुलना में अपने-अपने देश के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। लंदन स्थित मोबाइल एनालिटिक्स कंपनी ओपनसिग्नल की एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मोबाइल नेटवर्क एक्सपीरियंस रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो का स्कोर एक फीसदी बढ़कर 97.5 फीसदी तक पहुंच गया, जो लगभग छह महीने पहले 96.7 फीसदी था।रिपोर्ट में कहा गया, जियो का 97.5 फीसदी का 4जी उपलब्धता स्कोर सर्वाधिक है, जिसे हमने अपनी किसी भी रिपोर्ट में देश के स्तर पर दर्ज किया है। जियो की इतने कम समय में 97.5 फीसदी 4जी उपलब्धता तक पहुंचने की उपलब्धि वास्तव में आश्चर्यजनक है। ओपनसिग्नल ने कहा कि अमेरिका में दो ऑपरेटरों ने 90 फीसदी से अधिक स्कोर हासिल किया है, जबकि ताइवान में चार ऑपरेटर इस निशान से ऊपर हैं, लेकिन अभी तक किसी भी बाजार में किसी ने भी 95 फीसदी से ऊपर का स्कोर हासिल नहीं किया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि यहां तक कि यूरोप के सबसे विकसित मोबाइल बाजार माने जानेवाले नीदरलैंड में केवल एक ऑपरेटर ने 95 फीसदी का निशान पार किया है, और जापान में दो ऑपरेटरों ने इस बेंचमार्क को प्राप्त किया है। हालांकि, अध्ययन से पता चला है कि भारती एयरटेल ने 4जी उपलब्धता में सबसे बड़ी वृद्धि हासिल की है क्योंकि इसका स्कोर 10 फीसदी से अधिक बढ़कर 85 फीसदी से अधिक हो गया है।

बजाज ने लॉन्च की छोटी कार, 43 किमी का माइलेज देगी क्यूट

नई दिल्ली (एजेंसी) ।

देश की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने अपनी छोटी कार को लॉन्च कर दिया है. इस कार का ग्राहकों के बीच लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. बजाज क्यूट एक क्वॉड्रीसाइकल है, जिसे प्राइवेट का कामर्शियल दोनों तरह के व्हीकल के तौर पर रजिस्टर किया जा सकता है. क्यूट को कंपनी ने पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट में लॉन्च किया है. पेट्रोल वेरिएंट का एक्स-शोरूम प्राइज 2.48 लाख और सीएनजी वेरिएंट का एक्स-शोरूम प्राइज 2.78 लाख रुपये है. यानी सीएनजी वेरिएंट पेट्रोल से 30 हजार रुपये महंगा होगा. बजाज ने क्यूट को गुजरात, केरल, राजस्थान, यूपी और उड़ीसा में पहले ही लॉन्च कर दिया है. अब कंपनी ने इसे महाराष्ट्र में पेश किया है. महाराष्ट्र में दिल्ली के मुकाबले इसकी 15 हजार रुपये कम कीमत है. अपनी डिजाइन और यूज करने के आधार पर यह क्वाड्रीसाइकिल थ्री-व्हीलर रिक्शा व कार के बीच के सेगमेंट में जगह बना रहा है. क्यूट देश में क्वाड्रीसाइकिल सेग्मेंट की पहली गाड़ी है, जिसे सड़क और परिवहन मंत्रालय ने बाजार में उतारने की मंजूरी दी है. हालांकि, क्वाड्रीसाइकिल वाहनों को एक्सप्रेस वे पर उतरने की अनुमति नहीं होती. क्यूट क्वाड्रीसाइकिल में 216 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है. पेट्रोल इंजन 13.2 द्धश्च की पावर और 18.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क जेनरेट करता है. वहीं सीएनजी वेरिएंट 11 द्धश्च की पावर और 16.1 न्यूटर मीटर की टॉर्क जेनरेट करता है. यह 5 स्पीड सीक्यूएंटल मैन्युअल गियरबॉक्स से लैस है. क्वॉड्रीसाइकल क्यूट की लंबाई 2,752 एमएम, चौड़ाई 1,312 एमएम, लंबाई 1,652 एमएम और 1,925 एमएम का व्हीलबेस है।

आपको बता दें क्यूट देश की सड़कों पर फोर-व्हीलर में अब तक का सबसे छोटा प्रोडक्शन है. पेट्रोल इंजन वाली क्यूट का वजन 452 किलो है, वहीं सीएनजी वेरिएंट 504 किलो का है. कंपनी का दावा है कि क्यूट का पेट्रोल वेरिएंट 35 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है. वहीं सीएनजी वेरिएंट में माइलेज 43 किमी/किलो ग्राम है. क्यूट में 12 इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं. इसमें चार वयस्क के बैठने की अनुमति है. कंपनी ने बताया कि कार छह आकर्षक रंगों में बाजार में आएगी. बजाज ऑटो ने क्वाड्रीसाइकिल श्रेणी की क्यूट को 2012 में दिल्ली में आयोजित ऑटो शो में आरई60 के नाम से पेश किया था. देश में क्वाड्रीसाइकिल वाहनों को मंजूरी नहीं मिलने के कारण इस वाहन को बाजार में लॉन्च नहीं किया गया था. अब, जून 2018 में केंद्र सरकार ने क्वाड्रीसाइकिल की अलग श्रेणी को सूचीबद्ध कर इसे मंजूरी प्रदान कर दी है और 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर इसे भारतीय सड़कों पर उतारने की मंजूरी मिल गई।

बारडोली सीट पर न्यायपूर्ण एवं तटस्थ चुनाव कराने हेतु चुनाव तंत्र सुसज्ज

सूरत। गुरुवार को आगामी संसदीय चुनावों के मद्देनजर 23 अप्रैल होने वाले चुनावों 23 बारडोली संसदीय सीट पर चुनाव शान्तिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण, तटस्थ एवं पारदर्शक हो इस हेतु से 23 बारोडली संसदीय सीट का चुनाव अधिकारी एवं तापी जिला कलेक्टर आर. एस. निनामा की निगरानी में जिला प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियों को आखिरी स्वरुप दे दिया गया है। जिला चुनाव अधिकारी इस बैठक में समाविष्ट 7 विधान सभा विस्तारों का चुनाव अइधकारी ने चुनाव लक्षी कार्यवाही के विषय में सतत सूचना एवं मार्गदर्शन दे रहे है। विशेषत: रेण्डमाइजेशन, प्रिजाइडिग एवं पोलिंग बूथ आफीसरों की ट्रेनिंग सर्विस वाटर तथा ई.टी.पी.वी.एस. सम्बन्धित होने वाली कार्यवाही का आयोजन पोलिंग स्टाफ को पी.बी से मतदान, पुलिस स्टाफ को मतदान बूथ तक पहुंचाने की व्यवस्था ई.वी.एम. एवं वी.वी. पेट रकने हेतु स्टोंग रुम की तैयारी करना, चुनाव लक्षी मैटेरियल मतदान दिवस से पूर्व मतदान पर्चीयों का वितरण, ई.वी.एम. एवं वी.वी पेट का दूसरा रेण्डमाइजेशन, रिसीविंग एण्ड डिस्पैचिंग हेतु स्टाफ को ट्रेनिंग पी.डब्लू डी. मतदाताओं हेतु बूथ पर व्हील चेयर एवं सहायक उपलब्ध करवाना पोलिंग बूथ से 100 मीटर तथा 200 मीटर पर पट्टा बनाना तथा सिंगल विण्डो सिस्टम द्वारा विविध प्रचार नी परवानगियों समय मर्यादा में मिले इस हेतु एवं सीवीजिल उपर आने वाली फरियादों का समय सर निकाल करने सम्बन्धित विस्तृत समीक्षा की जा रही है। चुनाव के दिन 2202 मतदान मथकों पर फरज बजाने वाले अधिकारी कर्मचारीयों को मजसों की टीम द्वारा प्रत्यक्ष प्रदर्शन तथा थिपरिकल रुप से समझाकर ई.वी.एम एवं वी.वी पेट की झघन ट्रेनिग दी जा रही है।

आदर्श आचार संहिता, चुनाव देश रेख एवं नियन्त्रण प्रक्रिया खर्चीली कानूनी प्रक्रियाये एवं व्यवस्थाये लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की व्यवस्थाओं सहित चुनाव आयोग की विशेष सूचनाओं का विस्तृत मार्गदर्शन इस बैठक की जनरल आब्जर्वर डा. पूर्णिमा चौहाण एवं खर्च आब्जर्बर के.सी. कनौजिया भी चुनाव संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को दे रहे है। आम 23 बारडोली ससंदीय सीट का सामान्य चुनाव मुक्त एं न्यायी वातारवण में आयोजित हो एवं समृद्ध लोकतन्तर हेतु तमाम विषयों को चुस्त पालन के साथ लोकतन्त्र के इस महापर्व का उत्सव मनाने की सम्पूर्ण तैयारियों को चुनाव तत्र द्वारा अन्तिम रुप दिया जा रहा है।

परम पूज्य भक्तिसूरि समुदायवर्ती सा. अनन्त गुणाश्री म.सा. की निश्रामें एक ही स्थान, परमात्मा में पद्मावती मूर्ति विविधकारक, मंत्रोच्चार तथा एक ही साध्वीजी भगवतों आप की सभी ऐक्यता साथे सलंग 1 से लेकर 108 श्री पार्श्व पद्मावती पूजन चल रहा है। इनमें से आज 97वां पूजन सानन्द सम्पन्न हुआ।

बंगाल, मणीपुर में बम्पर वोटींग हुई

९५ सीट पर ६६ फिसदी से अधिक मतदान से सस्पेन्स

दुसरे दौर के मतदान के साथ ही अबतक कुल १८६ सीट पर मतदान संपन्न :६३५ उम्मीदवार के भावि सील

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दुसरे चरण में आज वोटींग संपन्न हुआ । दुसरे चरण में कश्मीर से कन्या कुमारी की ९५ सीटो पर मतदान हुआ । ११ राज्यो की ९५ सीट पर कुल ६६ प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ यद्यपि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मतदान कम रहा है । फिरभी अलग अलग राजकीय पक्षो ने अपनी और मतदान हुआ होने की बात कही है । वोटींग सुबह सात बजे से शुरु होने के बाद शांम तक चला । लोकसभा चुनाव के दुसरे चरण के मतदान पर सभी लोगों की नजर थी। खास करते तमिलनाडु में हुए मतदान पर सभी की नजर है । तमिलनाडु में आज ६१ प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ । जयललिता और करुणानिधि के अवसान के बाद पहली बार दो दिग्गज नेताओ की अनउपस्थिति में यह मतदान हुआ है । उत्तरप्रदेश की आठ सीटो पर आज मतदान हुआ । उत्तर प्रदेश में ५८ फिसदी से अधिक मतदान हुआ है। बंगाल में ७५ फिसदी से अधिक मतदान हुआ है । लोकसभा चुनाव के दुसरे चरण के लिए दोपहर तक मतदान की गति धीमी रही किन्तु उसके बाद मतदान में तेजी आई। आज के मतदान के साथ ही १६३५ उम्मीदवारो का भावि ईवीएम में सील हो गए है । लोकसभा चुनाव में प्रथम दो चरण में अब तक १८६ सीटो पर मतदान पूर्ण किया गया है अब तीसरे दौर में गुजरात की सभी २६ सीटों समेत मतदान होगा । २३ तारीख को तीसरे चरण में मतदान होगा ।

शहर के विभिन्न स्थलों पर चोरी की वारदाते

सूरत। गुरुवार को सूरत शहर में घर फोड़ चोरी की घटनाओं में चार घटनाओं में लगभग 5 लाख का मुद्दामाल चोर चुरा ले गए।

प्रथम घटना गोडादरा कैलाशनगर घर नं. 128/ए में अज्ञात चोरों ने दो मोबाईल फोन नकद 20,000 रुपये के साथ कुल 35000 के आसपास चोरी कर गये घर मालिक सर्वेश कैलासनाथ गुप्ता ने लिम्बायत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी है। दूसरी घटना पुजा आई माता रोड़ सर्शी रो हाउस के पास अक्षयपठत्र फाउन्डेशन में अज्ञात चोर ने वेल्डिंग मशीन प्लग होल्डर केबल सहित कुल 31,000 रुपये का माल चुरा लेगाया।

खर्च का हिसाब नहीं बताने वाले ८९ उम्मीदवारों को नोटिस भेजा

अहमदाबाद। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने २६ लोकसभा पर उम्मीदवारी कर रहे कुल ३७१ उम्मीदवारों में से ८९ उम्मीदवारों ने जिन्होंने चुनाव खर्च का हिसाब नहीं बता सकने से नोटिस भेजा गया है । गुजरात राज्य चुनाव आयोग की यह कड़ी कार्रवाई की वजह से राज्यभर में राज नीतिक हलचल तेज हो गई है । चुनाव आयोग की नोटिस की वजह से अब ८९ उम्मीदवारों को जरूरी जरूरी खुलासा और खर्च का हिसाब देना पड़ेगा । चुनाव आचारसंहिता के नियम अनुसार चुनाव के संदर्भ में होते खर्च की जानकारी चुनाव आयोग के समक्ष पेश करनी होती है । गुज रात राज्य की २६ लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी कर रहे ३७१ उम्मीदवारों में से ८९ उम्मीदवारों ने अपने चुनाव खर्च का हिसाब नहीं बताया, इस मामले को राज्य चुनाव आयोग ने बहुत ही गंभीरता से लिया और यह पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। राज्य चुनाव आयोग ने २६ सीटों पर ८९ उम्मीदवारों ने खर्च का हिसाब नहीं बताने पर नोटिस भेजा है। जिसमें से जामनगर सीट के सबसे ज्यादा १६ उम्मीदवार है।

कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ, गरीबों को 72000 देंगे : राहुल गांधी

अहमदाबाद । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज जूनागढ़ के वंथली में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने लोगों से जितने वादे किए थे, उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ करेगी और देश के 20 प्रतिशत गरीबों के खाते में रु. 72000 जमा करवाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश के उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए मोदी सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफी की जब बात आती है तो कहती है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी किसानों की बात करते हैं, परंतु किसानों के कर्ज माफी की बात आते ही मुंह फेर लेते हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता। कांग्रेस सरकार आई तो किसानों को सही अर्थों में न्याय मिलेगा। कांग्रेस सरकार साल के प्रारंभ में ही बता दे कि हम किसानों को कितनी रकम देंगे। हमारी सरकार किसानों के लिए अलग बजट बनाएगी। वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक जिलों के किसानों को खेती के बारे में जानकारी दे देंगे। मोदी ने 2014 के चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख खाते में डालने के बजाए मोदी सरकार ने नोटबंदी देश पर थोप दी और माता-बहनों को कतार में खड़ा कर दिया। इस कतार में एक भी उद्योगपति या धनी व्यक्ति को नहीं देखा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपने थिंक टैंक से कहा कि मोदी सरकार 15 लाख रुपए देने का वादा करती है, हम कितना दे सकते हैं। थिंक टैंक ने कुछ दिनों बाद मुझे रु. 72000 का आंकड़ा दिया। थिंक टैंक कहा कि देश के 20 प्रतिशत गरीबों को हम सालाना 72000 करोड़ दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीब परिवारों की महिलाओं के एकाउंट में 72000 रुपए सालाना जमा करवाएंगे। गरीबों के खाते में रुपए जमा होने पर बाजार में खरीदी बढ़ेगी और सही अर्थ में अर्थ तंत्र को गति मिलते ही देश में नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने देश में सालाना दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार देना तो दूर उल्टे नोटबंदी और जीएसटी लादकर लोगों के रोजगार छीन लिए। कांग्रेस सत्ता में आई तो हम एक जीएसटी कर देंगे। आज देश में पांच प्रकार के जीएसटी लिया जाता है, जिसे एक कर ढांचे में तब्दील कर देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में 22 लाख पद खाली हैं और उसे 2020 तक भर देंगे। हम 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा नहीं करते परंतु रिक्त पदों को भरने का भरोसा देता देते हैं। इसी के साथ पंचायतों में रिक्त पदों पर तत्काल भरा जाएगा। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री स्वयं इसे स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य के कई विभाग भ्रष्ट हैं। गुजरात में पिछले 25 साल से भाजपा की सरकार है। इस सरकार में जो खुद को चौकीदार बताते हैं, वह मुख्यमंत्री थे। यानी कि आपके मुख्यमंत्री की बात साबित होता है कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी आप सभी को मित्रों कहकर बुलाते हैं, जबकि अनिल अंबानी, निरव मोदी और मेहुल चौक्सी को भाई कहकर बुलाते हैं। फ्रांस सरकार के साथ राफेल का सौदा किया, जिसमें ज्यादा कीमत चुकाई गई है।

हनुमान जयंती पहले कैम्प हनुमान मंदिर से निकली शोभायात्रा अहमदाबाद में अलग-अलग क्षेत्र में घूमी। बड़ी संख्या में वाहनों के साथ लोग शामिल हुए।

डभोडिया मंदिर में ११११ तेल के डिब्बे का अभिषेक

आज हनुमान जयंती का पर्व भक्ति भाव से मनाया जाएगा

अहमदाबाद। शुक्रवार को चैत्र सुद पूर्णिमा और हनुमान जयंती का सुंदर योग होने से हनुमानजी भगवान के भक्तों में हनुमान जयंती का त्यौहार और पूजा, होम-हवन और यज्ञ को लेकर भारी उत्साह और भक्ति का माहौल है। शुक्रवार को हनुमान जयंती को लेकर सारंगपुर कष्टभंजन देवस्थान, गांधीनगर के प्रसिद्ध डभोडिया हनुमानजी, शाहीबाग के कैम्प हनुमानजी, एसजी हाइवे पर मारूति धाम, खाडिया के बाला हनुमान, बापूनगर के नागरवेल हनुमानजी मंदिर, मेमनगर के भीडभंजन हनुमानजी, थलतेज के पंचमुखी हनुमानजी मंदिर, मेमनगर गाम के पंचमुखी हनुमानजी मंदिर,सोला रोड पर कांकरिया हनुमानजी, वेजलपुर के जिज्ञासा सोसाइटी के पास भीडभंजन हनुमानजी मंदिर, लोदरा में प्रसिद्ध हनुमानजी मंदिर सहित के भगवान के मंदिरों में हनुमान भगवान का भव्य जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है। सारंगपुर कष्टभंजन देव मंदिर में शुक्रवार को सुबह में ७ बजे हनुमानजी भगवान का विशेष समूह यज्ञ आयोजित की जाएगी, जो दोपहर में १ बजे पूर्णाहुति होगी। गांधीनगर जिले के डभोडिया हनुमानजी मंदिर में तो भगवान को ११११ तेल के डिब्बे का अभिषेक, १५१ किलो की केक के प्रसाद और १०८ दीए की महाआरती सहित के कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया है।

शुक्रवार को चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती होने से भगवान के भक्तों में इसका महात्म्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। शहर के शाहीबाग कैम्प हनुमानजी मंदिर में हनुमान जयंती के दिन सुबह में ६.३० बजे हनुमानजी भगवान की भव्य आरती, १० बजे जन्मोत्सव, इसके बाद हनुमानजी को ५०० किलो दूध के हलवा का महाप्रसाद अर्पित किया जाएगा, ११ बजे कैम्प हनुमानमंदिर शिखर पर भगवान की ध्वजारोहण, १२ बजे से भक्तों के लिए भंडारा का आयोजन और शाम को ६.३० बजे महाआरती का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से सारंगपुर कष्टभंजन देवमंदिर में शुक्रवार को सुबह में ७ बजे से दोपहर में १ बजे तक हनुमानजी भगवान का विशेष यज्ञ होगा। सुबह में ९.३० बजे कष्टभंजन देव का भव्य अभिषेक किया जाएगा। सुबह में ११.३० बजे हनुमानजी भगवान को अन्नकुट का भोग लगाया जाएगा।

प्रहलादनगर पे एंड पार्क बंद होने पर पार्किंग की समस्या

अहमदाबाद। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शासकों द्वारा ट्राफिक नियमन के लिए नये दृष्टिकोण के तहत शहर में नया मल्टीलेवल पार्किंग प्रॉजेक्ट को लागू किया जा रहा है। जिसमें प्रहलादनगर गार्डन के सामने मल्टीलेवल पार्किंग भी शामिल है। प्रहलादनगर गार्डन के सामने म्युनिसिपल प्लोट में मल्टीलेवल पार्किंग बनने वाली है। हालांकि यह विशाल प्लोट का अभी तक पे एंड पार्क के तौर पर इस्तेमाल होने की वजह से प्रहलादनगर गार्डन के वीजिटर्स तथा आसपास के क्षेत्र के लोगों को पार्किंग के मामले में आशीर्वाद रूप था। लेकिन गत दिन से यह पे एंड पार्क को बंद कर दिया गया है, तब गर्मी वेकेशन में प्रहलादनगर गार्डन में वीजिटर्स की संख्या बढ़ने की वजह से उनके वाहन की पार्किंग सहित की समस्या ज्यादा जटिल बनने की संभावना है। जनता की परेशानी बढ़ाकर एएमसी प्रशासन और ट्राफिक शासकों ने पूरे मामले को नजरअंदाज कर रहे हो ऐसा चित्र सामने आ रहा है।

पे एंड पार्क बंद करने के बाद अब इस क्षेत्र में ट्राफिक पुलिस की लगातार चल रही टोइंग अभियान की वजह से विशेष करके टू व्हीलर चालकों की अब परेशानी और बढ़ने वाली है। यहां मल्टीलेवल पार्किंग बनाने में ढाई से तीन वर्ष लग जाने की वजह से पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था बिना प्रहलादनगर गार्डन के वीजिटर्स और आसपास के क्षेत्र के लोग पार्किंग कहां करेंगे यह बड़ी समस्या सामने आई है। प्रशासन द्वारा प्रहलादनगर गार्डन के सामने पे एंड पार्क में ८ मंजिल ऊंची मल्टीलेवल पार्किंग कॉम्पलेक्स बनाने के लिए दो-तीन दिन पहले १२ से १३ पेड़ को काटा गया था इसके बाद इसके दो गेट में से एक गेट को नील पतरे से बंद कर दिया गया। यहां के पे एंड पार्क का कॉन्ट्रैक्ट रद करने के बाद गत दिन से शासकों ने यह जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)